वर्ष-1 , अंक-14 | बेंगलुरु, गुरूवार , 03 सितम्बर 2026 | RNI NO:KNHIN/26/A5540 | Contact:news@bhaarataarth.com | पृठ - 4 ,मूल्य - 5 रुपए

दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

ख़बर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

नेपाल त्रासदी में भारत की मदद, संसद में बालेन शाह ने जताया आभार

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

काठमांडू, 2 सितंबर 2026। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़, मलबे और भूस्खलन से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के साथ हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस कठिन दौर में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में भारत और चीन की ओर से उपलब्ध कराई गई राहत एवं बचाव सहायता के लिए दोनों पड़ोसी देशों का आभार व्यक्त किया। नेपाल की संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा के समय अंतरराष्ट्रीय सहायता से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार ने आपदा के शुरूआती दौर में ही मित्र देशों, सुरक्षा एजेंसियों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय कर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। भारत-चीन की विशेषज्ञ टीमों का उल्लेख प्रधानमंत्री शाह के अनुसार, भारत और चीन ने आपदा की जानकारी मिलने के बाद विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों को नेपाल भेजा। इन टीमों ने शुरूआती चरण में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने और दुर्गम इलाकों तक बचाव दल पहुंचाने के संभावित मार्ग तलाशने में सहयोग किया। शाह ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य राहत कार्य करना भी बेहद कठिन था। भारी कीचड़, पत्थरों और मलबे के कारण कई स्थानों पर सुरक्षा बलों और बचावकर्मियों के लिए आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। उनके अनुसार, भारतीय विशेषज्ञों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से ऐसे कठिन क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। नेपाल सरकार के इस आकलन को दोनों देशों के बीच

आपदा के समय सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हजारों लोगों की तलाश जारी नेपाल सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आपदा में मृतकों की संख्या 1,127 तक पहुंच गई है, जबकि 4,858 लोगों के अब भी लापता होने की जानकारी दी गई है। सुरक्षा बलों, सेना और अंतरराष्ट्रीय बचाव दलों की संयुक्त कोशिशों से 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने का दावा किया गया है। हालांकि आपदा के बाद एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव अभियान में लगातार कठिनाइयां सामने आ रही हैं। प्रभावित परिवारों के लिए प्रत्येक बीतता दिन चिंता और अनिश्चितता बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर चिंता प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आपदा के व्यापक कारणों पर चर्चा करते हुए जलवायु परिवर्तन और हिमालयी पर्यावरण में हो रहे बदलावों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि भोटेकोशी नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और मलबे का प्रवाह सामान्य वर्षा की घटना से अलग था। नेपाल जैसे हिमालयी देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं। ग्लेशियरों में बदलाव, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन तथा बुनियादी ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। शाह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अधिक मजबूत वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने की अपील की। उनका तर्क है कि जलवायु परिवर्तन में कम योगदान देने वाले कई छोटे देश भी इसके गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। भारत की ओर से राहत एवं बचाव सहयोग नेपाल की आपदा के बाद भारत की ओर से राहत एवं बचाव के लिए विभिन्न विशेषज्ञ दल और आवश्यक सामग्री भेजे जाने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, टनल-रेस्क्यू विशेषज्ञों, चिकित्सकीय टीमों और आपातकालीन सहायता से जुड़े कर्मियों को नेपाल भेजा गया। इसके अतिरिक्त, आपदा में मारे गए लोगों की पहचान में सहायता के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डीएनए परीक्षण से संबंधित संसाधनों की मदद भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। ऐसी तकनीकी सहायता विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण होती है, जहां शवों की पहचान सामान्य तरीकों से संभव नहीं हो पाती।

भारत की ओर से राहत सामग्री में अस्थायी आश्रय के लिए टेंट, कंबल, स्वच्छता सामग्री, सौर लैंप, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और आवश्यक दवाएं शामिल होने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध आधिकारिक विवरण के अनुसार, भारतीय वायुसेना के विमानों से 70 टन से अधिक राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई गई है। राहत अभियान के दौरान भारतीय बचाव दलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि बचाव अभियानों से संबंधित अंतिम आंकड़ों का आकलन संबंधित सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। 24 घंटे समन्वय पर जोर नेपाल में जारी संकट के बीच भारत की ओर से राजनयिक और राहत समन्वय व्यवस्था को सक्रिय रखने की जानकारी दी गई है। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास तथा संबंधित संपर्क तंत्र के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखे जाने की बात कही गई है। प्राकृतिक आपदा की घड़ी में पड़ोसी देशों के बीच त्वरित सहयोग केवल मानवीय सहायता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने का भी माध्यम है। भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए ऐसी परिस्थितियों में सहयोग का महत्व और बढ़ जाता है। नेपाल की मौजूदा त्रासदी ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देशों को अपनी तैयारी कितनी मजबूत करनी होगी। राहत और बचाव तत्काल आवश्यकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित बुनियादी ढांचा, वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग भी उतना ही जरूरी है। आपदा की इस भयावह घड़ी में भारत की सहायता को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा संसद में व्यक्त किया गया आभार दोनों पड़ोसी देशों के बीच मानवीय सहयोग की अहमियत को रेखांकित करता है। संकट की घड़ी में पड़ोसी की मदद केवल कूटनीति नहीं, बल्कि मानवता की साझा जिम्मेदारी भी है।

मेकेदातु को जल्द मंजूरी की मांग, CWC चेयरमैन से मिले चालुवरायस्वामी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 2 सितंबर 2026। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री एन. चालुवरायस्वामी के नेतृत्व में राज्य के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग (CWC) के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष अनुपम प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में कर्नाटक की महत्वाकांक्षी मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना को आवश्यक तकनीकी एवं वैधानिक मंजूरियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया गया। बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, विभाग के सचिव कृष्णमूर्ति कुलकर्णी, मुख्य अभियंता महेश तथा केंद्रीय जल आयोग के जल नियोजन एवं परियोजना शाखा से जुड़े सदस्य योगेश पैठणकर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्री चालुवरायस्वामी ने मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग को सौंपे गए अनुपालन संबंधी विस्तृत दस्तावेजों पर चर्चा की। राज्य सरकार की ओर से परियोजना से संबंधित तकनीकी पहलुओं और आयोग द्वारा पहले उठाई गई आपत्तियों एवं टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी समीक्षा की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा कर परियोजना को आगे बढ़ाने में सहयोग किया जाना चाहिए। बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों पर जोर चालुवरायस्वामी ने मेकेदातु परियोजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट और वर्षा की कमी जैसी परिस्थितियों में इस प्रकार की जल भंडारण परियोजनाओं का महत्व बढ़ जाता है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रस्तावित संतुलन जलाशय से बेंगलुरु शहर और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने परियोजना से जलविद्युत उत्पादन की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। कर्नाटक सरकार का कहना है कि मेकेदातु जलाशय का उपयोग जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में किया जा सकता है।

कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा भी अहम

बैठक में कर्नाटक सरकार की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि प्रस्तावित संतुलन जलाशय से सूखे के वर्षों में कावेरी नदी के पानी के नियमन और प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे निर्धारित जल प्रवाह को व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने में सुविधा होगी।

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से जल विवाद का विषय रही है। इसलिए परियोजना की आगे की प्रगति केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी समीक्षा के साथ-साथ संबंधित कानूनी एवं अंतरराज्यीय पहलुओं पर भी निर्भर करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से परियोजना की तकनीकी समीक्षा को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया। हालांकि, परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिलने के लिए निर्धारित तकनीकी, पर्यावरणीय, कानूनी और अंतरराज्यीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होगा।

SCO में मोदी का कड़ा संदेश: आतंकवाद को हथियार न बनाएं

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बिश्केक, 2 सितंबर 2026। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट करते हुए सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी देश के लिए रणनीतिक लाभ या नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को केवल हमलों के जवाब तक सीमित रखने के बजाय उसके पूरे नेटवर्क पर प्रहार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकवादियों को मिलने वाले सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया। दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे

मानदंड की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद को समर्थन, संरक्षण या संसाधन उपलब्ध कराने वाली गतिविधियों के विरुद्ध सामूहिक एवं निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। उनका यह संदेश ऐसे समय आया है जब SCO के मंच पर भारत और पाकिस्तान सहित कई सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। सुरक्षा के साथ विकास पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को आर्थिक विकास तथा प्रगति की आधारभूत आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में किसी एक क्षेत्र में पैदा हुआ संघर्ष केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने SCO के माध्यम से सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक अवसरों के क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। संवाद और कूटनीति से समाधान की पैरवी पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए राजनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। SCO घोषणापत्र में भी आतंकवाद पर सख्ती SCO के बिश्केक घोषणापत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई गई। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताते हुए सदस्य देशों ने आतंकवाद के विभिन्न रूपों, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है, से मिलकर मुकाबला करने पर जोर दिया। SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों की सदस्यता के कारण आतंकवाद का मुद्दा इस क्षेत्रीय मंच पर विशेष महत्व रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भारत की सुरक्षा चिंताओं और आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। समाचार प्रेषकः अशोक कुमार सिंह

नेपाल में जलप्रलय: 1,127 मौतें, 4,858 लापता

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

काठमांडू, 2 सितंबर 2026। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। नेपाल पुलिस के अनुसार, अब तक 1,127 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4,858 लोग अभी भी लापता हैं। सुरक्षा बलों और राहत दलों ने प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। आपदा के बाद सुरक्षा बलों ने 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बरामद शवों की पहचान और उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस ने पहचान में सहायता के लिए 911 अज्ञात शवों का विवरण सार्वजनिक किया है, ताकि लापता लोगों के परिजन आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। चितवन में सबसे अधिक मौतें

बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 348 शव बरामद किए गए हैं। नवलपरासी पूर्व में 217, नवलपरासी पश्चिम में 190, नुवाकोट में 155, गोरखा में 66, धादिंग में 59, रसुवा में 45 और तनहूं में 38 लोगों की मौत दर्ज की गई है। भारत में भी नौ शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। मलबे में जिंदगी की तलाश

बाढ़ ने सड़क, पुल, मकान, जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। कई स्थानों पर मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने का काम चल रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बने मौसम संबंधी जोखिमों के बीच सुरक्षा बल लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार प्रभावित इलाकों में हजारों सुरक्षाकर्मी खोज, बचाव, राहत वितरण और बरामद शवों के प्रबंधन में लगाए गए हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी जारी है। जलविद्युत परियोजनाएं भी प्रभावित

आपदा से भोटेकोशी नदी के आसपास के क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं और संबंधित आधारभूत ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ परियोजनाओं की सुरंगों में लोगों के फंसे होने की आशंका के कारण बचाव अभियान विशेष चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल को राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता मिल रही है। बढ़ता मानवीय संकट

नेपाल में जारी आपदा अब गंभीर मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। प्रशासन के सामने एक ओर हजारों लापता लोगों की तलाश की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों को राहत, चिकित्सा सहायता और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। फिलहाल नेपाल में राहत एवं बचाव अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। अधिकारियों का प्रयास है कि मलबे और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक जल्द पहुंच बनाई जाए तथा बरामद शवों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा सके। समाचार प्रेषकः अशोक कुमार सिंह

ईरान-अमेरिका फिर आमने-सामने, तेल पर मंडराया संकट

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

वाशिंगटन/तेहरान, 2 सितंबर 2026। अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक महीने की अपेक्षाकृत शांति के बाद सैन्य तनाव फिर तेज हो गया है। अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर नई हवाई कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी हितों और अमेरिकी सहयोगी देशों से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले किए। दोनों देशों के बीच ताजा सैन्य आदान-प्रदान ने पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ा दी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, ताजा कार्रवाई में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, समुद्री संसाधन, संचार सुविधाओं और बारूदी सुरंग बिछाने से संबंधित क्षमताओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ईरानी गतिविधियों की प्रतिक्रिया बताया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों एवं सहयोगी देशों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जॉर्डन,

बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकाने प्रभावित हुए या वहां आने वाले हमलों को रोका गया। बहरीन और अन्य देशों ने कई ड्रोन एवं मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ी चिंता ताजा संघर्ष का सबसे गंभीर असर रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ रहा है। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां सैन्य तनाव बढ़ने से तेल एवं समुद्री परिवहन पर दबाव बढ़ गया है। हालिया घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और उतार-चढ़ाव देखा गया है। अमेरिकी कार्रवाई के पीछे ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों और समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगों से जुड़ी गतिविधियों को रोकने का तर्क दिया गया है। वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की बात कही है। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच होर्मुज में समुद्री सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। नागरिकों के हताहत होने की रिपोर्ट ईरान की ओर से दक्षिणी ईरान में एक विवाह समारोह के दौरान हुए हमले में नागरिकों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। अमेरिकी पक्ष ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है और नागरिकों को लक्ष्य बनाने से इनकार किया है। स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि अलग-अलग स्तर पर नहीं हो सकी है। SCOने जताई चिंता, कूटनीतिक समाधान पर जोर इस बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बिश्केक सम्मेलन में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। सदस्य देशों ने संघर्ष को बढ़ने से रोकने और विवादों के समाधान के लिए राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यमों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम अमेरिका-ईरान संघर्ष भारत के लिए भी रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में लंबे समय तक तनाव रहने और होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर भारत के आयात बिल, परिवहन लागत और महंगाई पर पड़ने की आशंका रहेगी। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई आगे बढ़ती है या दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं। संघर्ष का विस्तार होने की स्थिति में इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित न रहकर वैश्विक ऊर्जा बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। समाचार विश्लेषणः अशोक कुमार सिंह

दिल्ली में कारोबार आसान बनाने की तैयारी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल मंजूर

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नईदिल्ली, 2 सितंबर 2026। दिल्ली सरकार ने राजधानी में कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को सरल, तेज, पारदर्शी और कम खर्चीली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कारोबारियों और उद्यमियों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तथा विभिन्न सरकारी अनुमतियां प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाना है। बिल के माध्यम से अलग-अलग विभागों की प्रक्रियाओं को एकीकृत और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था में लाने का प्रस्ताव है। सिंगल विंडो बनेगा प्रमुख आधार प्रस्तावित कानून में सिंगल विंडो सिस्टम को महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से कारोबारी विभिन्न अनुमतियों, पंजीकरण, एनओसी और लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था में भवन योजना, अग्निशमन अनुमति, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी कारोबार से जुड़ी सेवाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। सभी कारोबारी मंजूरियों के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम

(डीएसआईआईडीसी) को एकल नोडल एजेंसी बनाए जाने की बात कही गई है। कुछ मामलों में आवेदन के साथ मंजूरी का प्रावधान बिल की अनुसूची-3 में शामिल निर्धारित गतिविधियों के लिए आवेदन के साथ ही स्वीकृति, अनुमति, लाइसेंस अथवा एनओसी देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। कम जोखिम वाली निर्धारित गतिविधियों और तय सीमाओं के मामलों में स्व-घोषणा को स्वीकार करने का भी प्रावधान रखा गया है। बार-बार पंजीकरण से राहत प्रस्तावित कानून में पहले से सरकारी व्यवस्थाओं के तहत पंजीकृत उद्यमों पर दोहराव वाले पंजीकरण का बोझ घटाने की योजना है। सरकार के अनुसार जीएसटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), एमएसएमई कानून या श्रम संहिताओं के तहत पंजीकृत उद्यमों को कुछ अतिरिक्त व्यापार संबंधी पंजीकरणों से राहत दी जा सकती है। इसका उद्देश्य कारोबारियों से बार-बार समान जानकारी और दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया को कम करना है। तीन वर्ष तक सामान्य निरीक्षण नहीं बिल में निरीक्षण व्यवस्था को भी अधिक जोखिम-आधारित और विश्वास-केंद्रित बनाने का प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार किसी उद्यम के पंजीकरण के बाद तीन वर्ष तक सामान्य निरीक्षण नहीं करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। हालांकि गंभीर शिकायत या विशेष परिस्थितियों में निरीक्षण की अनुमति रहेगी।'

सम्पादकीय

धैर्य, क्षमा और विवेक ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति

आज के तेज रफ्तार जीवन में मनुष्य के पास सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन धैर्य लगातार कम होता दिखाई देता है। सड़क पर मामूली विवाद हो, कार्यस्थल पर मतभेद हो या परिवार में किसी बात को लेकर असहमति–छोटी-सी बात कई बार बड़े तनाव और संघर्ष का कारण बन जाती है। ऐसे समय में भारतीय जीवन-दर्शन का एक सरल संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है–हर बात का जवाब क्रोध से देना आवश्यक नहीं है। महाभारत से प्रेरित एक लोकप्रिय प्रसंग इसी जीवन-दृष्टि को सहजता से समझाता है। कथा में एक यात्रा के दौरान अर्जुन को एक असभ्य सहयात्री के व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उसके व्यवहार से भीम क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन अर्जुन धैर्य बनाए रखते हैं। उनका तर्क सरल है–यात्रा छोटी है, कुछ समय बाद सभी अपने-अपने मार्ग पर चले जाएंगे। ऐसे क्षणिक व्यवहार के कारण अपने मन की शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं है। यही संदेश आज के समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जीवन वास्तव में एक यात्रा है और इस यात्रा में मिलने वाले अनेक लोग स्थायी रूप से हमारे साथ नहीं रहते। कोई हमें सम्मान देता है, कोई आलोचना करता है; कोई सहयोगी बनता है तो कोई चुनौती बनकर सामने आता है। लेकिन हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को अपने मन पर स्थायी अधिकार दे देना हमारे ही मानसिक संतुलन के लिए हानिकारक हो सकता है। क्रोध स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन क्रोध के वश में होकर लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। वास्तविक शक्ति दूसरे को पराजित करने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन पर नियंत्रण स्थापित करने में है। बाहुबल का प्रदर्शन क्षणिक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन संयम और विवेक व्यक्ति के चरित्र की स्थायी पहचान बनते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में यह सीख और अधिक प्रासंगिक हो गई है। एक टिप्पणी, एक संदेश या किसी विचार से असहमति कई बार तीखी बहस और व्यक्तिगत कटुता का रूप ले लेती है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, विचार करना और दूसरे पक्ष को समझने का प्रयास करना शायद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं है और धैर्य का अर्थ अन्याय को स्वीकार कर लेना भी नहीं है। जहां अधिकारों, सम्मान और न्याय की रक्षा आवश्यक हो, वहां दृढ़ता से खड़ा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यक्तिगत अहंकार और क्षणिक उत्तेजना के कारण विवाद को बढ़ाना विवेकपूर्ण आचरण नहीं कहा जा सकता। जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को हराने में नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी विजय अपने भीतर उठ रहे क्रोध, अहंकार और आवेश पर नियंत्रण पाने में होती है। यही आत्मसंयम व्यक्ति को परिपक्व बनाता है और समाज में संवाद, सहिष्णुता तथा सौहार्द को मजबूत करता है। जीवन सीमित समय की यात्रा है। इस यात्रा में हर व्यक्ति किसी न किसी पड़ाव पर हमारा सहयात्री बनता है। इसलिए छोटी-छोटी बातों को जीवन का बड़ा संघर्ष बनाने के बजाय धैर्य, क्षमा और प्रेम के साथ आगे बढ़ना अधिक सार्थक है। सच्ची वीरता दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाने में है। यही छोटे सफर की सबसे बड़ी सीख और जीवन की सबसे बड़ी जीत है।

तेल की तपिश और रुपया: भारत की अर्थव्यवस्था की अग्निपरीक्षा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

विश्व अर्थव्यवस्था आज जिस दौर से गुजर रही है, उसमें किसी एक क्षेत्र का संकट दूसरे देशों की आर्थिक सेहत को प्रभावित करने में देर नहीं लगाता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता अब भारत के लिए भी महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती बनती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती के बावजूद वैश्विक तेल कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल का दबाव बना हुआ है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी विकास यात्रा में ऊर्जा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन से लेकर उद्योग, कृषि, विमानन और दैनिक उपभोग तक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ईंधन की कीमतों से प्रभावित होता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उथल-पुथल केवल पेट्रोल-डीजल की कीमतों का प्रश्न नहीं रह जाती, बल्कि यह महंगाई, व्यापार घाटे, रुपये की विनिमय दर और आम नागरिक की जेब से जुड़ा विषय बन जाती है। ताजा अंतरराष्ट्रीय बाजार संकेतों के अनुसार ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत करीब 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंची है। यह तेजी ऐसे समय में है जब पश्चिम एशिया में तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बाजार की चिंताओं को बढ़ाया है। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उसके कच्चे तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री मार्गों से आता है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे वातावरण में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। रुपये में अनावश्यक उतार-चढ़ाव रोकने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। रिपोर्टों के अनुसार, आरबीआई ने रुपये को सहारा देने के लिए डॉलर की बिक्री बढ़ाई है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत स्थिति इस चुनौती से निपटने में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है–क्या केवल विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे लंबे समय तक बाहरी आर्थिक दबाव को टाला जा सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। भंडार संकट के समय सुरक्षा कवच अवश्य है, लेकिन स्थायी समाधान अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती में है। भारत को आयातित ऊर्जा पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करनी होगी और घरेलू ऊर्जा स्रोतों तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा। भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। इसी क्रम में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य भी चर्चा में है। सरकार और उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए भारी निवेश, कुशल मानव संसाधन और वित्तीय नियमों में आवश्यक सुधार की जरूरत होगी। यह बदलाव केवल पर्यावरण की दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी वैश्विक संकट में अर्थव्यवस्था को असुरक्षित बना सकती है। इसलिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय आर्थिक नीति के रूप में देखना होगा।

दूसरी चुनौती आम नागरिक की है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका प्रभाव परिवहन लागत, माल ढुलाई और उत्पादन लागत के माध्यम से व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। हालांकि घरेलू ईंधन कीमतों पर तत्काल और समान प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है, फिर भी लंबे समय तक ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतें महंगाई के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। ऐसे समय में सरकार और केंद्रीय बैंक के सामने संतुलन साधने की चुनौती है। रुपये को स्थिर रखना जरूरी है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक हस्तक्षेप भी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। राजकोषीय अनुशासन, मजबूत निर्यात, घरेलू उत्पादन, ऊर्जा विविधीकरण और निवेश का विस्तार–ये सभी मिलकर अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। भारत के लिए वर्तमान परिस्थिति एक चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि वैश्विक घटनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था अब अलग-थलग नहीं रह सकती। अवसर इसलिए कि ऊर्जा संक्रमण, विनिर्माण, तकनीक और घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में निर्णायक कदम उठाकर भारत अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। आज आवश्यकता घबराने की नहीं, बल्कि दूरदर्शिता से नीति बनाने की है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार तत्काल सुरक्षा दे सकता है, लेकिन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था ही दीर्घकालिक सुरक्षा देती है। रुपये की मजबूती केवल मुद्रा बाजार की उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्पादन, निर्यात, रोजगार और विश्वास की संयुक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भारत की आर्थिक अग्निपरीक्षा जारी है। यदि ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भर उत्पादन को एक साथ आगे बढ़ाया गया, तो वैश्विक संकट भारत के लिए केवल चुनौती नहीं रहेगा–वह आत्मनिर्भर और अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था के निर्माण का अवसर भी बन सकता है।

बारूद के साये में दुनिया: युद्ध नहीं, शांति की जरूरत

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां किसी एक क्षेत्र का सैन्य संघर्ष पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य टकराव ने पश्चिम एशिया में तनाव को और गहरा कर दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े सैन्य ठिकानों, वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यह स्थिति केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया पहले से ही अनेक राजनीतिक और सैन्य तनावों से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी नए हमले की प्रतिक्रिया यदि व्यापक होती है, तो उसका असर तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार, महंगाई और वैश्विक बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है। यह दुनिया के प्रमुख ऊर्जा मार्गों में शामिल है। रॉयटर्स के अनुसार, हालिया संघर्ष के दौरान इस मार्ग से सोमवार को लगभग 1.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का परिवहन हुआ, जबकि जहाजों पर हमलों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने समुद्री परिवहन को लेकर आशंकाएं बढ़ाई हैं। तेल की कीमतों में तेजी का सीधा प्रभाव दुनिया के उन देशों पर पड़ सकता है जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति विशेष महत्व रखती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। पहले से महंगाई और रोजगार जैसी चुनौतियों से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध का लंबा खिंचना किसी अतिरिक्त बोझ से कम नहीं होगा। लेकिन किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान शेयर बाजार या तेल की कीमतों में नहीं, बल्कि मानवीय जीवन में होता है। पश्चिम एशिया से सामने आ रही घटनाओं में नागरिकों के हताहत होने की खबरें चिंता बढ़ाती हैं। एक कथित हमले में विवाह समारोह के दौरान नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है, हालांकि ऐसे मामलों में अंतिम तथ्य स्थापित करने के लिए स्वतंत्र और आधिकारिक जांच आवश्यक है। यही वह बिंदु है जहां विश्व समुदाय को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। सैन्य शक्ति किसी देश की सुरक्षा का साधन हो सकती है, लेकिन स्थायी शांति का विकल्प नहीं। मिसाइल का जवाब दूसरी मिसाइल से देने की रणनीति संघर्ष को रोकने के बजाय उसे और विस्तृत कर सकती है। आज आवश्यकता ऐसे कूटनीतिक प्रयास की है जिसमें अमेरिका, ईरान और क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली देश संवाद का रास्ता खुला रखें। भारत के लिए भी यह समय संतुलित और व्यावहारिक कूटनीति का है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत संवाद और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने में रही है। पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। दुनिया को यह समझना होगा कि आधुनिक युद्ध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। एक क्षेत्र में शुरू हुआ संघर्ष तेल बाजार के माध्यम से दूसरे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और समुद्री मार्गों में व्यवधान हजारों किलोमीटर दूर बैठे उपभोक्ताओं तक महंगाई पहुंचा सकता है। वैश्विक बाजारों में ऊर्जा कीमतों और बांड बाजारों को लेकर बढ़ती चिंता इसका संकेत दे रही है। आज विश्व के सामने असली परीक्षा यह नहीं है कि किस देश के पास अधिक सैन्य शक्ति है। असली परीक्षा यह है कि क्या शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति का उपयोग युद्ध बढ़ाने के बजाय युद्ध रोकने के लिए कर सकते हैं? मानव सभ्यता ने दो विश्व युद्धों और अनेक क्षेत्रीय संघर्षों की भारी कीमत चुकाई है। इतिहास यह सिखाता है कि युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन उसके परिणामों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए पश्चिम एशिया में तत्काल युद्धविराम, नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और गंभीर कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता की पहचान है। आज दुनिया को बारूद की भाषा से अधिक संवाद, संयम और कूटनीति की भाषा की जरूरत है। यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय समय रहते तनाव कम करने में सफल होता है, तो यह केवल पश्चिम एशिया की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी।

बारिश का कहर और व्यवस्था की परीक्षा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

भारत में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, खेती, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की व्यवस्था से जुड़ा विषय है। इस वर्ष भी देश के अनेक हिस्सों में बारिश ने जहां किसानों और जलस्रोतों के लिए राहत की उम्मीद जगाई है, वहीं कई राज्यों में भारी वर्षा, जलभराव और तेज हवाओं ने प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। बारिश प्रकृति का वरदान है, लेकिन जब शहरों की नालियां पानी का दबाव संभालने में असमर्थ हो जाएं, सड़कें जलमग्न हो जाएं और नदी-नालों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचने लगे, तो वही बारिश आपदा का रूप ले लेती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितनी बारिश हुई, बल्कि यह भी है कि प्रशासन और स्थानीय निकाय उस बारिश से निपटने के लिए कितने तैयार थे। देश के अनेक शहर तेजी से फैल रहे हैं। कंक्रीट का विस्तार बढ़ रहा है, प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते कम हो रहे हैं और जलाशयों तथा तालाबों पर बढ़ता दबाव भविष्य के लिए गंभीर संकेत है। हर वर्ष मानसून आने से पहले नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां करने की बात होती है, लेकिन बारिश के दौरान वही समस्याएं फिर सामने आ जाती हैं। यह स्थिति केवल किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की आलोचना का विषय नहीं, बल्कि शहरी नियोजन की दीर्घकालिक कमजोरी का संकेत है।

ग्रामीण भारत के लिए बारिश का महत्व अलग है। खेती का बड़ा हिस्सा अब भी मानसून पर निर्भर है। पर्याप्त और समय पर वर्षा किसानों के लिए अच्छी फसल की उम्मीद पैदा करती है, जबकि अत्यधिक वर्षा खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मौसम की अनिश्चितता अब कृषि नीति के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे समय में सरकारों की प्राथमिकता केवल राहत बांटने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपदा प्रबंधन का अर्थ है–पहले से तैयारी, समय पर चेतावनी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षित निकासी व्यवस्था और प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाना। तकनीक ने मौसम पूर्वानुमान को काफी बेहतर बनाया है। मोबाइल संदेश, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और मीडिया के माध्यम से समय रहते लोगों को सावधान किया जा सकता है।

विशेष चिंता उन परिवारों की होनी चाहिए जो निचले इलाकों, नदी किनारे या कमजोर मकानों में रहते हैं। भारी बारिश के दौरान सबसे अधिक जोखिम इन्हीं वर्गों को होता है। आपदा के समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने केवल घर और सामान बचाने की चुनौती नहीं होती, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और रोजगार तक का संकट खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। मौसम संबंधी चेतावनी को हल्के में लेना, जलभराव वाले रास्तों से जबरन गुजरना या नदी-नालों के किनारे अनावश्यक रूप से जाना जोखिम बढ़ा सकता है। प्रशासन और जनता के बीच सहयोग ही आपदा के प्रभाव को कम कर सकता है।

भारत के लिए अब समय आ गया है कि मानसून को केवल हर साल आने वाली प्राकृतिक घटना मानकर उससे निपटने की पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़ा जाए। जल संरक्षण, वर्षाजल संचयन, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, प्राकृतिक जलमार्गों का संरक्षण और मजबूत स्थानीय आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना होगा। बारिश को रोका नहीं जा सकता और न ही प्रकृति को नियंत्रित करने का दावा किया जा सकता है। लेकिन उसके प्रभाव को कम करने की तैयारी निश्चित रूप से की जा सकती है। आधुनिक भारत की विकास यात्रा तभी सार्थक होगी, जब उसके शहर जलभराव से और गांव बाढ़ व फसल क्षति से सुरक्षित हों। आज जरूरत बारिश से डरने की नहीं, बल्कि उसके साथ जीने की वैज्ञानिक व्यवस्था बनाने की है। प्रकृति अपना काम करेगी; अब प्रशासन और समाज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी।

विधानसभा भंग कर चुनाव लड़ें: विजयेंद्र

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

मास्की (रायचूर), 2 सितंबर 2026। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर दलितों, पिछड़े वर्गों और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार को विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनता और वंचित वर्गों को न्याय देने में विफल रही है तो उसे जनादेश के लिए दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए। बेल्लारी चलो पदयात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के दावों के बावजूद सरकार इन वर्गों को पर्याप्त न्याय नहीं दे पा रही है। विजयेंद्र ने वाल्मीकि निगम से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले का उल्लेख करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। हालांकि, इन आरोपों और मामलों की अंतिम स्थिति संबंधित जांच, सरकारी रिकॉर्ड तथा कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है

और आने वाले दिनों में सरकार के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर कर्नाटक के कई क्षेत्रों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। विजयेंद्र के अनुसार, कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है और किसानों को सिंचाई तथा पशुओं के लिए चारे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर सवाल विजयेंद्र ने राज्य सरकार की सूखा प्रबंधन नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले से ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की समस्याओं को उठा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरों को लेकर भी टिप्पणी की और दावा किया कि सरकार भाजपा के आंदोलन के बाद अधिक सक्रिय हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सीमित संख्या में तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, जबकि भाजपा के अनुसार राज्य के अन्य कई क्षेत्र भी सूखे की गंभीर स्थिति से प्रभावित हैं।

किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाया विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य में आम नागरिकों को सरकारी कामकाज के दौरान भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन आरोपों और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने रायचूर और उत्तर कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में पेयजल, पशुचारा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। भाजपा नेता ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति अपना रवैया नहीं बदलती है तो उसे राजनीतिक रूप से जनता के असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सरकार की ओर से विजयेंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। राजनीतिक आरोपों के बीच संबंधित मामलों की जांच और तथ्यात्मक स्थिति का निर्धारण आधिकारिक रिकॉर्ड तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।

सूखा घोषित करने में भी रिश्वत का आरोप: विजयेंद्र

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

मास्की (रायचूर), 2 सितंबर 2026। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर किसानों, दलितों, युवाओं और गरीबों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पदयात्रा के दूसरे दिन मास्की में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में गंभीर सूखे की स्थिति के बावजूद इसे सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया गया है। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि यदि मास्की के किसान बड़ी रकम की रिश्वत दें, तो सरकार इस क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने पर विचार कर सकती है। हालांकि, भाजपा नेता के इस आरोप पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आने तथा तथ्यों की आधिकारिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। SEP-TSP निधि के उपयोग पर उठाए सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति उपयोजना (एसईपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की निधियों को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने

आरोप लगाया कि इन योजनाओं के हजारों करोड़ रुपये अन्य विभागों में स्थानांतरित किए जाने से दलित समुदाय के विकास से जुड़ी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। विजयेंद्र ने कहा कि इन निधियों का उपयोग दलित समुदाय के लिए आवास, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जा सकता था। उन्होंने सरकार पर दलितों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की मांग की। वाल्मीकि निगम मामले का भी किया उल्लेख विजयेंद्र ने वाल्मीकि विकास निगम से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा पदयात्रा और आंदोलन की घोषणा के बाद राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। उन्होंने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों और दलित नेताओं से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि क्या दलित नेताओं और समुदाय के हितों की रक्षा को लेकर सरकार का रवैया वास्तव में गंभीर है। किसानों और गरीबों की उपेक्षा का आरोप भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार को दलितों, गरीबों और किसानों के हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि राज्य में जनता का असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से भाजपा के आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। विजयेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना, 108 एम्बुलेंस सेवा और दलित बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य किए थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा किसानों, दलितों और गरीबों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। राजनीतिक आरोपों और दावों के बीच संबंधित मामलों की वास्तविक स्थिति सरकारी दस्तावेजों, जांच रिपोर्टों और कानूनी प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट होगी।

एक मंच पर गूंजे भक्ति के स्वर, राजस्थानी समाजों की महिला मंडलियां एकजुट

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

शिवमोग्गा, 2 सितंबर 2026। शिवमोग्गा में प्रवासी राजस्थानी जैन समाज और राजस्थानी विष्णु समाज की महिला भजन मंडलियों ने पहली बार एक ही मंच पर सामूहिक रूप से भक्ति कार्यक्रम की तैयारी का अभ्यास किया। पूर्व

उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के सानिध्य में मंगलवार, 1 सितंबर को उनके निवास स्थान पर आयोजित इस सामूहिक अभ्यास सत्र में विभिन्न महिला भजन मंडलियों ने उत्साह और उमंग के साथ अपनी प्रस्तुतियां दीं।

प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले अभ्यास कार्यक्रम में दोनों समाजों की महिला मंडलियों ने सामूहिक रूप से भजनों का अभ्यास किया। आयोजकों के अनुसार, शिवमोग्गा में राजस्थानी जैन समाज और राजस्थानी विष्णु समाज की महिला भजन मंडलियों का इस प्रकार एक मंच पर आना अपने आप में विशेष अवसर रहा। अलग-अलग मंडलियों की महिलाओं ने अपनी-अपनी तैयारियों और भक्ति भाव के अनुरूप प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जन्माष्टमी पर होगा मुख्य आयोजन

आयोजकों ने बताया कि मंगलवार का कार्यक्रम मुख्य आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक अभ्यास सत्र था। इसका मुख्य कार्यक्रम भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शनिवार, 5 सितंबर 2026 को वासवी स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। महिला भजन मंडलियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजकों की ओर से आने-जाने के लिए बस की व्यवस्था भी की गई। अभ्यास सत्र के बाद सभी प्रतिभागियों के लिए ईश्वरप्पा के निवास पर भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजन में सहयोग देने वालों का सम्मान कार्यक्रम के संचालन और व्यवस्थाओं में दिनेशदास वैष्णव (चाय वाला) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंच पर श्री कान्तेश द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा महिलाओं में श्रीमती नन्दा बेन, रेखा बेन तथा संतोषी माता की परम भक्त गीता बेन का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर माताजी और भगवान के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इसके बाद महिला भजन मंडलियों ने सामूहिक फोटो खिंचवाए और बसों के माध्यम से अपने-अपने घरों के लिए रवाना हुईं।

आरक्षण नहीं, समान अवसर की पुकार!

न जाति के नाम पर कोई छोटा-बड़ा हो, न धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव हो।
न क्षेत्र की सीमा किसी की राह रोके, हर युवा अपने सपनों की ऊँचाई छू सके।
जिसने मेहनत की, उसका सम्मान हो, प्रतिभा के आगे न कोई व्यवधान हो।
गरीब की झोली में अवसर भी आए, मेहनती हाथों को आगे बढ़ने का मौका मिल पाए।
न जाति देखी जाए, न धर्म पूछा जाए, न प्रदेश देखकर अवसर रोका जाए।
हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, हर युवा को मेहनत का पूरा आधार मिले।
नीति ऐसी हो जो कमजोर को संभाले, और मेहनत करने वालों को भी आगे निकाले ।
न किसी का हक छीने, न किसी को दबाए, न्याय की व्यवस्था सबको समान अवसर दिलाए ।
भारत की पहचान विविधता में महान है, हर नागरिक के सपनों का एक समान मान है।
आओ मिलकर ऐसा समाज बनाएं, जहाँ योग्यता और मेहनत का सम्मान बढ़ाएं।
न जाति-पात, न धर्म का भेद, न क्षेत्रवाद की कोई दीवार । समान अवसर, समान सम्मान - यही हो भारत का सच्चा अधिकार ।

अनिल सिंह सिकरवार

संस्कारों संग शिक्षा की उड़ानः डॉ. निधि राजपुरोहित

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों, संस्कारों और

सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात कर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए राजपुरोहित समाज कर्नाटक एवं बेंगलुरु राजपुरोहित संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 450 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मैसूरु रोड स्थित राजपुरोहित समाज भवन में आयोजित समारोह में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान के साथ बालिका शिक्षा और उच्च शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. निधि राजपुरोहित ने विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राजपुरोहित समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बालिका की शिक्षा केवल उसके व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे संस्कारित और शिक्षित पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। डॉ. निधि राजपुरोहित ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि शिक्षा के दौरान उन्हें माता-पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिला, जिसने उन्हें उच्च शिक्षा और पीएचडी तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जड़ें अपनी, पंख अपने और उड़ान अपनी विषय पर विचार रखते हुए कहा कि मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों के साथ उत्कृष्ट भविष्य के सपने देखने चाहिए। उन्होंने सामाजिक लिंग भेद समाप्त कर बालिकाओं को उनकी रुचि और इच्छा के अनुरूप शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की अपील की। साथ ही कहा कि आज की पीढ़ी को माता-पिता, परिवार और समाज के सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित रखना चाहिए। डॉ. मीना राजपुरोहित ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। शिक्षाविद् राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने कहा कि शिक्षा वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है और समाज का प्रभावी मार्गदर्शन तभी संभव है, जब समाज स्वयं शिक्षित और जागरूक बने। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रशासनिक और अन्य सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए गंभीरता से तैयारी करने का आान किया। बेंगलुरु में कार्यरत जीएसटी अधिकारी सचिन राजपुरोहित ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को मंच पर पुरस्कार देना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा और भविष्य के लिए प्रेरणा देना भी है। उन्होंने 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य में उच्च शिक्षा के विभिन्न विकल्पों और करियर मार्गदर्शन के लिए समाज स्तर पर एक मंच विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान पीढ़ी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर अपनी राय रखने से पहले तथ्यों को समझना और जांचना आवश्यक है। केवल बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राजपुरोहित सेवा न्यास, मुंबई के प्रबंध ट्रस्टी खेतसिंह मवड़ी ने बेंगलुरु की दोनों संस्थाओं द्वारा शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महानगर जैसे बेंगलुरु में समाज के बच्चों को सम्मानित होते देखना गर्व और संतोष का विषय है। इससे पूर्व बेंगलुरु राजपुरोहित संघ के अध्यक्ष भंवरसिंह राजपुरोहित ने अतिथियों एवं उपस्थितजनों का स्वागत किया, जबकि राजपुरोहित समाज कर्नाटक के अध्यक्ष नारायणसिंह राजपुरोहित ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दोनों संस्थाओं की ओर से अतिथियों का सम्मान भी किया गया। बीकानेर से विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानाध्यापक किशोरसिंह राजपुरोहित ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने की इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इसरो के सहायक तकनीकी अधिकारी वीरेन्द्रसिंह, गरुड़ कमांडो अशोकसिंह राजपुरोहित, आर्मी स्कूल के कार्यालय अधीक्षक विकास राजपुरोहित सहित अन्य शिक्षाविदों और अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 450 से अधिक विद्यार्थियों का हुआ सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 1 से 8 तक 80 प्रतिशत से अधिक अंक, कक्षा 9 से 12 तक 75 प्रतिशत से अधिक अंक तथा डिग्री स्तर पर 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में कुल 450 से अधिक छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्त करते ही नन्हे-मुन्ने बच्चों और विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके साथ आए अभिभावकों ने भी गौरव और प्रसन्नता व्यक्त की। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के साथ अन्य बच्चों में भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। मंच संचालन किशोरसिंह राजपुरोहित के साथ शोभा एवं भावना ने किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में राजपुरोहित समाज और संघ से जुड़े अनेक युवाओं एवं युवतियों ने विशेष सहयोग प्रदान किया। समाचार प्रेषकः सुरेन्द्र राजपुरोहित बेंगलुरु

विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति की दुर्गा पूजा तैयारी बैठक 6 सितंबर को

भारतार्थ खबर ईं१ं३ं१३ॅंज्ञ

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। बेंगलुरु में आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के अनुसार, यह बैठक रविवार, 6 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे, माननीय श्री अभिषेक ब्रह्मर्षि जी की गौशाला में आयोजित होगी। समिति ने बताया कि बैठक में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों, आयोजन की रूपरेखा तथा विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और सदस्यों को गौ माता की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. जितेंद्र कुमार जीतू दुबे ने सभी भगवत प्रेमियों, भागवत भक्तों तथा समिति के भाई-बहनों और मातृशक्ति से बैठक में उपस्थित होने की अपील की है। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। समिति के अनुसार, जो सदस्य गौशाला तक सामूहिक रूप से जाना चाहते हैं, वे रविवार सुबह 10 बजे तक विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति के हेड ऑफिस, येलहंका न्यू टाउन पहुंच सकते हैं। वहां से सभी सदस्य एक साथ गौशाला के लिए प्रस्थान करेंगे। विशेष रूप से माताओं, बहनों और उन सदस्यों के लिए, जिन्हें गौशाला तक सीधे पहुंचने में असुविधा हो सकती है, समिति द्वारा आवागमन की व्यवस्था करने की बात कही गई है। पं. जितेंद्र कुमार जीतू दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति ने सभी श्रद्धालुओं और सदस्यों से इस महत्वपूर्ण बैठक में सहभागिता कर दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियों को सफल बनाने का आग्रह किया है। समाचार प्रेषकः जितेंद्र कुमार दुबे, बेंगलुरु

रिश्वत ऑडियो वायरल, तीन SI निलंबित

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पसंदीदा स्थान पर पुलिस तैनाती के लिए कथित रूप से रिश्वत देने संबंधी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने तीन उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में हलियाल में कानून-व्यवस्था उपनिरीक्षक के पद पर तैनाती हासिल करने के लिए धनराशि देने को लेकर बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। लगभग दो मिनट की इस रिकॉर्डिंग के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।

रिकॉर्डिंग में शामिल अधिकारियों के आपस में मित्र होने तथा एक ही तालुक में तैनाती पाने की कथित चर्चा भी सामने आई है। ऑडियो की प्रामाणिकता और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच विभागीय स्तर पर की जा रही है। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम.एन. दीपन के निर्देश पर संबंधित तीनों उपनिरीक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आरोपों और ऑडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े तथ्यों की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस बीच, जनता दल (सेक्युलर) के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा उक्त रिकॉर्डिंग साझा किए जाने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। पार्टी ने सत्तारूढ़ सरकार पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि, मामले में अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। पुलिस विभाग की कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि तैनाती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी कथित अनियमितता के आरोप की जांच प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी।

राहुल गांधी की FIR पर कांग्रेस का हल्ला बोल

भारतार्थ खबर **Bhaarataarth.com**

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने उत्तराखंड में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने किया। प्रदर्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य

सिद्धारमैया, एआईसीसी सचिव गोपीनाथ पलानीअप्पन तथा केपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष विनय कुमार सोरके सहित कई मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर अनुचित है और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास है। पार्टी ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान की मांग की। फ्रीडम पार्क में आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति समर्थन व्यक्त किया और विरोध दर्ज कराया। हालांकि, एफआईआर से जुड़े आरोपों और मामले की कानूनी प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

दलित मुद्दों पर विजयेंद्र का सरकार पर हमला, पदयात्रा का ऐलान

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने दलित समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दलित समुदाय के नेताओं के साथ संवाद के दौरान उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों, एससीपी/टीएसपी निधि, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषयों को लेकर सरकार को घेरा। विजयेंद्र ने दावा किया कि भाजपा की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर राज्य सरकार दबाव में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का समय पर दौरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दूसरे चरण में और अधिक तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने की मांग उठाई जाएगी। दलित कल्याण निधि को लेकर सवाल विजयेंद्र ने दावा किया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में दलित समुदाय के कल्याण के लिए करीब 800 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। उनके अनुसार वर्तमान कांग्रेस सरकार ने विभिन्न विकास निगमों और बोर्डों को अपेक्षित राशि का

पूरा हिस्सा जारी नहीं किया। उन्होंने देवराज उर्स विकास निगम, अंबिगे चौधरी विकास निगम, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम सहित अन्य संस्थाओं के लिए धन आवंटन और वास्तविक जारी राशि में अंतर होने का आरोप लगाया। विजयेंद्र ने कहा कि बजट में घोषित राशि और वास्तविक रूप से जारी धनराशि के बीच अंतर की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। गारंटी योजनाओं में एससीपी-टीएसपी राशि के इस्तेमाल का आरोप भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए निर्धारित एससीपी/टीएसपी निधि का इस्तेमाल गारंटी योजनाओं के लिए किया। उन्होंने इसे दलित समुदाय के हितों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से निधि के उपयोग पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की। विजयेंद्र ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर दलित समुदाय में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और भाजपा अपनी प्रस्तावित पदयात्रा के दौरान इस विषय को प्रमुखता से उठाएगी। आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार के रोजगार और आरक्षण संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ढाई लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और घुमंतू समुदायों से संबंधित आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं रहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरक्षण से जुड़े मामलों में सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी पक्ष नहीं रखा। पदयात्रा में उठेंगे जनहित के मुद्दे विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा की पदयात्रा के दौरान दलितों, पिछड़े वर्गों और अन्य प्रभावित समुदायों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी शोषित एवं प्रभावित लोगों की आवाज बनने का प्रयास करेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दलित एवं पिछड़े समुदायों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के कार्यकाल में विभिन्न समुदायों के लिए लागू की गई योजनाओं का हवाला दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रताप गौड़ा पाटिल सहित दलित समुदाय के नेता एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

केपीसीसी में उत्तर कर्नाटक पर मंथन, चार जिलों के नेता जुटे

भारतार्थ खबर **Bhaarataarth.com**

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) कार्यालय में उत्तर कर्नाटक के चार जिलों–रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और विजयनगर–के कांग्रेस प्रतिनिधियों, जिला अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ड्ढउउ अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने की। बैठक में संबंधित जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े संगठनात्मक विषयों और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखी। बैठक में अव्उउ सचिव गोपीनाथन पलानियप्पन, KPCC कार्यकारी अध्यक्ष वसंत कुमार, पूर्व मंत्री एच. अंजनेया, पूर्व सांसद वी.एस. उग्रप्पा, विधायक हंपनगौड़ा बदरली, विधायक अन्नपूर्णा, तुकाराम, विधायक बसवनगौड़ा दद्दल, हंपय्या नायक, बसवनगौड़ा थुरुविहाल तथा विधान परिषद

सदस्य एन.एस. भोसराज सहित कई नेता शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक डी.एस. हुलागेरी समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक एवं कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। जिला संगठन पर विशेष चर्चा बैठक में बेल्लारी ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवयोगी, बेल्लारी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आलम प्रशांत, विजयनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिराज शेख, कोप्पल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरेगौड़ा बय्यापुरा तथा रायचूर सहित अन्य जिलों के कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला एवं विधानसभा स्तर पर संगठन को अधिक सक्रिय बनाने, कार्यकताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने पर चर्चा होने की जानकारी दी गई। उत्तर कर्नाटक के चार महत्वपूर्ण जिलों के पार्टी नेताओं की इस बैठक को क्षेत्र में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है।

टॉडगढ़ भैरव भक्ति में डूबा बेंगलुरु

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। मेवाड़ जैन मित्र मंडल, बेंगलुरु की ओर से पैलेस मैदान स्थित प्रिंसेस श्राइन सभागार में आयोजित एक शाम टॉडगढ़ काला गोरा भेरुजी के नाम भक्ति संध्या में श्रद्धालु देर रात तक भैरव भक्ति में लीन रहे। ज्योत प्रकट होते ही भेरुजी के जयकारों से पूरा सभागार गुंजायमान हो उठा।

कार्यक्रम का आयोजन भैरव धाम टॉडगढ़ के मुख्य उपासक कपिल पडियार, विद्या प्रकाश पडियार एवं रतनलाल सेन के पावन सानिध्य में किया गया। आयोजन के प्रारंभ में भव्य भैरव दरबार सजाया गया। उपासकों एवं लाभार्थी परिवारों द्वारा विधिवत ज्योत प्रकट कर पूजा-अर्चना की गई। ज्योत प्रकट होते ही श्रद्धालुओं ने भेरुजी के जयकारों के साथ अपनी आस्था प्रकट की। पूजा के उपरांत आरती हुई, जिसमें पूरा सभागार भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भावों में डूबा नजर आया। उपासकों ने ज्योत एवं भक्ति गीतों के माध्यम से भैरव बाबा का स्मरण किया। इसके बाद आयोजित भक्ति संध्या का शुभारंभ भैरव चालीसा के पाठ एवं गणपति वंदना के साथ हुआ। राजस्थान से पहुंचे भजन कलाकार भगवत सुथार ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भैरव भक्ति से ओतप्रोत भजनों पर श्रद्धालुओं ने तालियों और जयकारों के साथ उत्साहवर्धन किया। भगवत सुथार की प्रस्तुति के दौरान वातावरण विशेष रूप से भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु भजनों की धुन पर भाव-विभोर होकर झूमते और भाव नृत्य करते दिखाई दिए। आयोजक मंडल के युवा सदस्य भी भक्ति गीतों की मधुर धुनों पर थिरकते नजर आए। जोधपुर से आईं गायिका दिव्या वैष्णव ने भी भैरव भक्ति से जुड़े विभिन्न भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। उनकी प्रस्तुतियों के साथ देर रात तक सभागार में भक्ति का प्रवाह बना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदारिया जैन ओसवाल साजनान संघ के अध्यक्ष ललित मांडोत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जैन ओसवाल साजनान संघ संस्था मदारिया आंजनेश्वर के अध्यक्ष ईश्वरलाल श्रीमाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में संस्था के महामंत्री महावीरकुमार पोकरणा तथा मदारिया जैन ओसवाल साजनान संघ के मंत्री सुरेशकुमार गन्ना शामिल रहे। अतिथियों का मेवाड़ जैन मित्र मंडल की ओर से संयोजक दीपक भटेवरा, प्रवीण दक, संतोष भटेवरा, अमृत दलाल, गौतम मांडोत सहित अन्य पदाधिकारियों ने सम्मान किया। भैरव दरबार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

सभागार में सजाए गए भव्य भैरव दरबार के दर्शन के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक दरबार के समक्ष शीश नवाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते नजर आए। अनेक श्रद्धालुओं ने ज्योत के दर्शन कर परिवार एवं समाज में सुख-शांति की कामना की। लाभार्थी परिवारों का किया सम्मान

कार्यक्रम संयोजक दीपक भटेवरा ने बताया कि भक्ति संध्या का आयोजन अनेक लाभार्थी एवं सहयोगी परिवारों के योगदान से संभव हुआ। मंडल की ओर से साफा, माला एवं स्मृति चिह्न भेंट कर लाभार्थी परिवारों को सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य प्रायोजक हगामीलाल दिनेशकुमार चावत परिवार, प्रसादी प्रायोजक रोशनलाल अशोककुमार चावत परिवार, वेन्यू प्रायोजक रोशनलाल नवनीत वागरेचा परिवार, ऑडियो-वीडियो प्रायोजक मंजुबाई रोशनलाल भटेवरा परिवार, लॉजिस्टिक प्रायोजक सरिता कैलाश दलाल परिवार, श्रृंगार लाभार्थी मधु मुकेश बमबोरी परिवार तथा मीडिया प्रायोजक महेन्द्रकुमार दीपक गन्ना परिवार सहित सह-प्रायोजक एवं सिल्वर प्रायोजक परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर टॉडगढ़ काला गोरा भेरुजी के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित की। समाचार प्रेषकः सुरेन्द्र राजपुरोहित, बेंगलुरु

आईएमएफ जाने से पहले राहुल जैन ने लिया गुरु आशीर्वाद

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राहुल जैन को वॉशिंगटन डी.सी. स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। राहुल जैन आगामी 13 सितंबर को दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अमेरिका प्रस्थान से पूर्व राहुल जैन बेंगलुरु के ज्ञानोदय परिसर पहुंचे और निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज के दर्शन कर उनका मंगल आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर मुनिश्री ने उनके नए दायित्व के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं। वीरसागर जी महाराज ने कहा कि पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ व्यक्ति की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में मूल संस्कारों, नैतिक मूल्यों और अनुशासन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने राहुल जैन को नए दायित्व में देश की गरिमा के अनुरूप कार्य करने तथा भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों को जीवन में बनाए रखने की प्रेरणा दी। हिंदी माध्यम से आईएएस और अब अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी राहुल जैन की शैक्षणिक यात्रा जबलपुर में हिंदी माध्यम से शुरू हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। अब आईएमएफ में भारत की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनके प्रशासनिक करियर का एक उल्लेखनीय पड़ाव माना जा रहा है।

गुरु सान्निध्य में राहुल जैन ने कहा कि उनके जीवन में परिवार से मिले संस्कार और गुरुजनों का मार्गदर्शन निरंतर प्रेरणा का स्त्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर परिश्रम व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।

धार्मिक संस्कारों से जुड़ा परिवार

राहुल जैन का परिवार धार्मिक संस्कारों से जुड़ा रहा है। वे वर्तमान में विदिशा में विराजमान क्षुल्लक श्री 105 तत्वसागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के पुत्र बताए गए हैं। उनकी माताजी भी प्रतिमा धारण कर धार्मिक एवं व्रतशील जीवन का पालन कर रही हैं।

बताया गया कि राहुल जैन को बाल्यावस्था में पूज्य आचार्य गुरुदेव से पिच्छी ग्रहण करने का अवसर मिला। वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ अपने प्रशासनिक जीवन में भी धार्मिक अनुशासन को महत्व देते रहे हैं। विदेश में भी धर्म-ध्यान की निरंतरता का भाव वीरसागर जी महाराज ने बताया कि अमेरिका में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल जैन ने वहां मंदिर दर्शन, पूजन और धर्म-ध्यान की व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेने की इच्छा व्यक्त की। मुनिश्री ने इसे उनके धार्मिक संस्कारों और अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक बताया।

उन्होंने कहा कि व्यावसायिक और प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी व्यक्ति अपने जीवन-मूल्यों और धार्मिक अनुशासन को कायम रख सकता है। सफलता और संस्कार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मजबूत करने वाले तत्व हो सकते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा

राहुल जैन की हिंदी माध्यम की शिक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक की यात्रा युवाओं के लिए प्रेरक संदेश देती है। इस अवसर पर गुरु महाराज ने कहा कि युवा सफलता के साथ संस्कार, नैतिकता और आत्मअनुशासन को भी जीवन का हिस्सा बनाएं।

बेंगलुरु में गूंजेगी बाबा रामदेवजी की भक्ति

भारतार्थ खबर **Bhaarataarth.com**

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। फूलों की नगरी बेंगलुरु में श्री मेघवाल समाज संघ, बेंगलुरु कर्नाटक की ओर से आगामी 13 सितंबर 2026 को एक शाम श्री बाबा रामदेवजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन भादवा शुक्ल द्वितीया के अवसर पर आयोजित होने वाले सातवें वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम रविवार, 13 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे से पार्वती कन्वेंशन हॉल, राजाजीनगर इंडस्ट्रियल टाउन में आयोजित होगा। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन कलाकार लाखाराम भादरू एंड पार्टी द्वारा बाबा रामदेवजी की महिमा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भक्ति संध्या के दौरान विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियों का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम में श्री बाबा रामदेवजी के पवित्र घोड़े की पूजा-अर्चना भी विधि-विधान से की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक बोलियों का आयोजन भी प्रस्तावित है। श्री मेघवाल समाज संघ, बेंगलुरु कर्नाटक एवं बेंगलुरु प्रवासी मेघवाल समाज की ओर से समाज के सभी बंधुओं एवं श्रद्धालुओं से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक

और सामाजिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे, प्रेम और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाने का माध्यम हैं। उन्होंने सभी समाज बंधुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा रामदेवजी की भक्ति में सहभागी बनने और सातवें वार्षिक महोत्सव को सफल बनाने का आग्रह किया है। श्री मेघवाल समाज संघ के पदाधिकारियों एवं समस्त कार्यकारिणी ने समाज बंधुओं से कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाने की अपील की है। समाचार प्रेषकः सुजाराम मेघवाल, बेंगलुरु

राम मंदिर ट्रस्ट की कमान अब एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के हाथ

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

अयोध्या, 2 सितंबर 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किए जाने को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। उनकी नियुक्ति को मंदिर परिसर और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के प्रशासनिक संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में लंबे और वरिष्ठ कार्यकाल के बाद इसी वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने करीब 39 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं दीं। सेवा के दौरान वे पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वायुसेना में लंबा अनुभव जितेंद्र मिश्रा के सैन्य करियर में संचालन, नेतृत्व और रणनीतिक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें लगभग 3,000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के कारण प्रशासनिक और संगठनात्मक प्रबंधन में उनका अनुभव भी व्यापक माना जाता है। उनके कार्यकाल

से जुड़े सैन्य अभियानों को लेकर भी विभिन्न रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भूमिका का उल्लेख सामने आया है। टाइगर हिल और ऑपरेशन सफेद सागर से जुड़े अभियानों में भी उनकी भूमिका बताए जाने की जानकारी उपलब्ध है। हालांकि सैन्य अभियानों से संबंधित संवेदनशील विवरणों की आधिकारिक पुष्टि केवल संबंधित रक्षा संस्थानों के अधिकृत बयानों के आधार पर ही मानी जानी चाहिए। पहले उएड की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। मंदिर प्रशासन, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, तीर्थयात्रियों की सुविधाएं, निर्माण एवं विकास परियोजनाएं, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियां व्यापक प्रशासनिक ढांचे की मांग करती हैं। ऐसे में ट्रस्ट के स्तर पर पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पेशेवर बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। हालांकि CEO की जिम्मेदारियों और अधिकारों का वास्तविक स्वरूप ट्रस्ट की आधिकारिक व्यवस्था और आदेशों से ही स्पष्ट होगा। सैन्य नेतृत्व से प्रशासनिक जिम्मेदारी तक भारतीय वायुसेना में शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी संभाल चुके अधिकारी का धार्मिक एवं तीर्थ प्रशासन से जुड़े संगठन में आना अपने आप में उल्लेखनीय है। सैन्य सेवा के दौरान विकसित अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता, संकट प्रबंधन और बड़े स्तर पर समन्वय का अनुभव किसी भी बड़े संस्थान के प्रशासन में उपयोगी हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ शहर में धार्मिक पर्यटन और तीर्थ गतिविधियों का विस्तार हुआ है। ऐसे में मंदिर से संबंधित व्यवस्थाओं के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से लागू करना ट्रस्ट के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। आगे बढ़ेगी प्रशासनिक व्यवस्था जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि राम मंदिर ट्रस्ट अपनी बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। आने वाले समय में उनकी भूमिका मंदिर की दैनिक प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न परियोजनाओं के समन्वय और ट्रस्ट के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण हो सकती है। राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थल बन चुका है। ऐसे में पारदर्शी, सुव्यवस्थित और जवाबदेह प्रशासन इसकी दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होगा। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के साथ अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ट्रस्ट के नए प्रशासनिक ढांचे में उनकी जिम्मेदारियां किस प्रकार निर्धारित होती हैं और अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन से नए कदम उठाए जाते हैं।

पंजाब में कांग्रेस का चुनावी बिगुल, 10 दिन में राहुल गांधी का दौरा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

चंडीगढ़, 2 सितंबर 2026। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन और चुनावी अभियान को गति देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले 10 दिनों के भीतर पंजाब का दौरा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनके दौरे का कार्यक्रम लगभग तैयार है और जल्द ही इसकी विस्तृत घोषणा की जा सकती है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस इसे चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकताओं में सक्रियता बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रही है। मीडिया अभियान को मजबूत करने की तैयारी दौरे की तैयारियों को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ बैठक की। बैठक के बाद AICC के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि

पंजाब में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीम को भी राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि चुनावी अभियान और मीडिया समन्वय को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी 23 जिलों में मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। इसका उद्देश्य पार्टी के अभियान को जिला और जमीनी स्तर तक व्यवस्थित करना है। गुटबाजी के सवाल पर नेतृत्व का संदेश पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी मतभेदों को लेकर पूछे गए सवाल पर गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने माना कि राजनीतिक दलों में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक रहने वाले आंतरिक मतभेद किसी भी संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की कोशिश सभी नेताओं और कार्यकताओं को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने की है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को इसी राजनीतिक एकजुटता और चुनावी सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। नशा, रोजगार और शिक्षा पर फोकस कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए नशे की समस्या, शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा को प्रमुख मुद्दों में शामिल करने के संकेत दिए हैं। पार्टी इन विषयों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के खिलाफ अपना राजनीतिक अभियान तेज करने की तैयारी में है।

बिहार में 47 पुलों और 55 राज्य पथों पर टोल की तैयारी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

पटना, 2 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में सड़क एवं पुलों के उपयोग के लिए पथ उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) वसूली की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के निर्णय के अनुसार पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबे 47 पुलों और 55 राज्य उच्च पथों को पथ उपयोगकर्ता शुल्क वसूली के लिए चिह्नित किया गया है। हालांकि, इन स्थानों पर तत्काल टोल वसूली शुरू नहीं होगी। इसके लिए यातायात सर्वे, टोल प्लाजा निर्माण और आवश्यक तकनीकी ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। टोल से पहले होगा यातायात सर्वे चिह्नित पुलों और सड़कों पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या का आकलन करने के लिए यातायात सर्वे

कराया जाएगा। सर्वे में वाहनों की संख्या के साथ उनके प्रारंभिक स्थान और गंतव्य से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसी आधार पर प्रत्येक सड़क और पुल के लिए टोल प्लाजा की उपयुक्त जगह निर्धारित की जाएगी। यातायात दबाव और सड़क की लेन के अनुरूप प्लाजा का आकार तय किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग सुविधा भी शामिल होगी। 30.95 करोड़ रुपये की सलाहकार सेवा टोल व्यवस्था के लिए शुल्क दर निर्धारित करने, वसूली की निगरानी और विभिन्न टोल परियोजनाओं को समन्वित रूप से संचालित करने के लिए सलाहकार सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस पर अनुमानित 30 करोड़ 94 लाख 71 हजार 500 रुपये खर्च होंगे। फास्टैग व्यवस्था के लिए आवश्यक उपकरण एवं कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने में तकनीकी संस्था की सहायता ली जाएगी। तैयारियां पूरी होने के बाद टोल वसूली के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा और इसके बाद चयनित सड़कों एवं पुलों पर शुल्क वसूली शुरू की जाएगी। नगर निकायों को 9,169 करोड़ रुपये का अनुदान कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के नगर निकायों को कुल 9,169 करोड़ रुपये का बेसिक एवं परफॉरमेंस अनुदान उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी। इस राशि का आवंटन जनसंख्या और नगर निकायों के स्व-स्रोत राजस्व के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। पटना नगर निगम को विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम का लाभ मिलने का भी प्रावधान है। समग्र शहरी विकास योजना पांच साल और जारी राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत सड़क, जल निकासी, पार्किंग, फुटपाथ और प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य किए जाएंगे। झील, पार्क, घाट और जलाशयों के विकास को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये की राशि से योजनाओं का चयन किया जाएगा और क्रियान्वयन बुडको के माध्यम से किया जाएगा। नेहरू पथ चौड़ीकरण को 39.80 करोड़ की मंजूरी पटना के नेहरू पथ को डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक करीब 7.20 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ा करने के लिए 39.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना में सड़क चौड़ीकरण के साथ नाला एवं फुटपाथ से संबंधित कार्य, चहारदीवारी का स्थानांतरण, करीब पांच किलोमीटर ग्रिल लगाने, उपयोगिताओं और पेड़ों की शिफ्टिंग तथा सड़क सुरक्षा संकेतक लगाने का प्रावधान है। बिहार मंत्रिमंडल के इन निर्णयों से राज्य में सड़क एवं पुलों के रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की नई व्यवस्था के साथ-साथ शहरी आधारभूत ढांचे और परिवहन सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। टोल व्यवस्था लागू होने से पहले आवश्यक सर्वेक्षण, तकनीकी तैयारी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

बेंगलुरु में साफा-पुष्पहार से सीआई लक्ष्मण सिंह चम्पावत का सम्मान

भारतार्थ खबर **Bhaarataarth.com** बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। राजपूत समाज कर्नाटक की ओर से चामुंडा माता मंदिर में सीआई लक्ष्मण सिंह चम्पावत, आबूरोड के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों और समाजबंधुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। समारोह में लक्ष्मण सिंह चम्पावत को पुष्पहार पहनाकर तथा पारंपरिक राजपूती साफा धारण करवाकर सम्मानित किया गया। समाजबंधुओं ने उनके कर्तव्यनिष्ठा एवं सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए

शुभेच्छाएं व्यक्त कीं। कार्यक्रम में आबूरोड के ओमप्रकाश बिश्नोई राइडर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भी सीआई चम्पावत का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। सामाजिक एकता पर जोर समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रतिभावान और जिम्मेदार व्यक्तियों का सार्वजनिक सम्मान युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और समाजहित के कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। समाजबंधुओं ने कहा कि सामाजिक संगठनों की मजबूती आपसी सहयोग और विश्वास से संभव है। इस अवसर पर समाजहित में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा भाईचारे की भावना को और मजबूत करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। समारोह में राजपूत समाज कर्नाटक के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे। स्वागत एवं सम्मान का यह कार्यक्रम हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समाचार प्रेषकः दलपतसिंह भायल, बेंगलुरु

पर्युषण में आहार नहीं, आत्मसंयम बने साधना का आधार

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, बसवनगुडी के तत्वावधान में चातुर्मास के लिए विराजित प. पू. साध्वी श्री प्रियश्रद्धांजना श्री जी म. सा. ने कहा कि पर्युषण जैसे लोकोत्तर पर्व आत्मसंयम, तप और आत्मचिंतन की साधना के अवसर हैं। इन दिनों में आहार का त्याग, रसत्याग और वृत्ति संक्षेप अपनाकर व्यक्ति अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास कर सकता है। ध्यान शतक ग्रंथ की विवेचना करते हुए साध्वीश्री ने कहा कि मनपसंद भोजन मिलने पर भी व्यक्ति को समभाव बनाए रखना चाहिए। प्रिय भोजन की अत्यधिक प्रशंसा अथवा अप्रिय भोजन की निंदा भी मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और जैन दर्शन के अनुसार ऐसी मानसिक प्रतिक्रियाएं कर्म बंधन का कारण बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसी क्रिया के बाद उत्पन्न होने वाली आसक्ति या द्वेष की प्रतिक्रिया व्यक्ति को कर्मों के बंधन की ओर ले जाती है। भोजन की आसक्ति से बचने का संदेश साध्वीश्री ने आहार संज्ञा को मानव जीवन की गहरी आसक्तियों में से एक बताते हुए कहा कि शरीर निरंतर किसी न किसी रूप में आहार पर निर्भर रहता है। जैन दर्शन में ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार का उल्लेख मिलता है। इनमें

कवल अर्थात भोजन के प्रति जीव की आसक्ति विशेष रूप से प्रबल मानी गई है। उन्होंने कहा कि भोजन के प्रति अत्यधिक आकर्षण व्यक्ति के विवेक को प्रभावित कर सकता है। कई बार स्वाद और पसंद की आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति आहार की शुद्धता, मयार्दा और उसके पीछे की भावना पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता। साध्वीश्री ने कहा कि आत्मा के वास्तविक पोषण का माध्यम स्वाध्याय, धमार्राधना और आध्यात्मिक साधना है। पर्युषण पर्व में बाहरी खान-पान की अपेक्षा आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता देने का संदेश निहित है। तप से रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण उन्होंने श्रद्धालुओं से पर्युषण के दौरान अपनी क्षमता के अनुसार आयम्बिल, उपवास और एकाशना जैसे तप करने का आान किया। उनके अनुसार तप का उद्देश्य केवल भोजन कम करना नहीं, बल्कि रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना और मन को संयमित करना है। साध्वीश्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार वाहन में एक बार ईंधन भरने के बाद वह लंबे समय तक चल सकता है, उसी प्रकार शरीर को बार-बार भोजन की आदत डालने के बजाय आहार में संयम का अभ्यास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भोजन और नींद ऐसी आदतें हैं, जिन्हें जितना बढ़ाया जाता है, उनकी प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ती जाती है और संयम से उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामान्य लौकिक पर्व प्रायः खान-पान और मनोरंजन के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन पर्युषण महापर्व का स्वरूप इससे अलग है। यह आत्मसंयम, तप, स्वाध्याय, क्षमा और आत्मचिंतन का पर्व है। इसलिए इस दौरान आहार संयम और इन्द्रिय निग्रह को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। संसार में विवेक ही आध्यात्मिक सहारा साध्वीश्री ने संसार की प्रकृति को लवण समुद्र के उदाहरण से समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार समुद्र का जल चारों ओर से खारा होता है, उसी प्रकार संसार में भी मोह, आसक्ति और अनेक प्रकार के आकर्षण व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गहराई में उतरने का साहस करता है, उसे मोती भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक महत्वपूर्ण अपनी दृष्टि और प्रतिक्रिया को बदलना है। समभाव, संयम और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पर्युषण के अवसर पर दिया गया यह संदेश श्रद्धालुओं को आहार और इन्द्रिय सुखों की आसक्ति से ऊपर उठकर आत्मकल्याण, तप और धमार्राधना की ओर प्रेरित करता है। समाचार प्रेषकः ललित डाकलिया, बेंगलुरु

समुद्र का बढ़ता जलस्तरः मुंबई-कोलकाता के 1.4 करोड़ लोगों पर खतरा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

मुंबई, 2 सितंबर 2026। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव अब तटीय महानगरों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समुद्र के लगातार बढ़ते जलस्तर से दक्षिण एशिया के निचले तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है।

मुंबई, कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका विशेष रूप से संवेदनशील शहरों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन क्षेत्रों में 1.4 करोड़ से अधिक लोगों के घर, आजीविका और जीवन पर दीर्घकालिक खतरा मंडरा रहा है। 2024 में समुद्र-स्तर वृद्धि ने बनाया रिकॉर्ड संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2014 से 2023 के दौरान वैश्विक समुद्र-स्तर औसतन 4.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ा, जबकि 2024 में यह बढ़ोतरी बढ़कर रिकॉर्ड 5.9 मिलीमीटर पहुंच गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं। साथ ही गर्म होता समुद्री जल फैलता है, जिससे समुद्र का स्तर और ऊपर उठता है। इसका असर केवल तटीय बस्तियों तक सीमित नहीं है। बढ़ते समुद्री जलस्तर से सड़क, परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा तंत्र, इमारतों, जल प्रणालियों और भूजल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। समुद्री जल के भीतर आने से भूजल और कृषि भूमि के खारे होने का खतरा भी बढ़ता है। मुंबई और कोलकाता क्यों संवेदनशील मुंबई और कोलकाता घनी आबादी वाले तटीय महानगर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों शहरों को ढाका के साथ उन निचले डेल्टा क्षेत्रों में शामिल किया है, जहां समुद्र-स्तर बढ़ने से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है। रिपोर्ट में यह खतरा किसी निश्चित वर्ष की भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जलवायु जोखिम के तौर पर सामने रखा गया है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर बाढ़ की आवृत्ति और तटीय तूफानों के प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। इससे बंदरगाहों, व्यापार, मत्स्य पालन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। हिमालय भी बढ़ा रहा दक्षिण एशिया का जोखिम समुद्र-स्तर वृद्धि के साथ दक्षिण एशिया के लिए हिमालयी ग्लेशियरों में बदलाव भी चिंता का विषय है। हिमालय को अक्सर एशिया के महत्वपूर्ण जल-स्रोत क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से शुरूआती दौर में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जबकि दीर्घकाल में जल उपलब्धता में कमी से सूखे, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर दबाव पड़ सकता है। खतरे से निपटने के लिए अभी से तैयारी जरूरी संयुक्त राष्ट्र का संदेश स्पष्ट है कि समुद्र-स्तर में कुछ वृद्धि अब अपरिहार्य हो चुकी है, लेकिन भविष्य में वृद्धि की मात्रा और उसके प्रभाव को सीमित करने की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। इसके लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के साथ तटीय शहरों में जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षित निर्माण, जल प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाना जरूरी होगा। जलवायु परिवर्तन का यह संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है। यह आने वाले समय में आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मानव विस्थापन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए समय रहते दीर्घकालिक जलवायु-लचीली योजनाएं तैयार करना आवश्यक है।

FIR के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 2 सितंबर 2026। उत्तराखंड में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के नेतृत्व में बुधवार को फ्रीडम पार्क में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता राज्य के सभी जिलों में विरोध दर्ज करा रहे हैं। हरिप्रसाद ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आान करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा अन्याय और दमन के खिलाफ संघर्ष की रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के दौर के राजनीतिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए कार्यकताओं से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट

रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उनके अनुसार, कांग्रेस कार्यकताओं को केवल विरोध तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दों पर व्यापक जनजागरण करना चाहिए। खड़गे के सम्मान का मुद्दा भी उठाया बी.के. हरिप्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे मामलों में संगठित और प्रभावी ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कांग्रेस के ऐतिहासिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी का मूल उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान ने समाज के वंचित वर्गों को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष का आान हरिप्रसाद ने कहा कि संविधान लागू होने से पहले समाज के अनेक वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक अवसरों में असमानताओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समानता और अधिकारों का आधार प्रदान किया है। उन्होंने कार्यकताओं से संविधान, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आान किया।

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में स्मार्टफोन पर रोक

भारतार्थ खबर **Bhaarataarth.com**

चेन्नई, 2 सितंबर 2026। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में अब स्मार्टफोन लेकर प्रवेश करना आसान नहीं होगा। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में कैमरा युक्त मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लागू कर दी है। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई है। हालांकि, कैमरा रहित साधारण मोबाइल फोन को मंदिर परिसर में ले जाने की अनुमति है। नई व्यवस्था के तहत स्मार्टफोन लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रवेश द्वारों पर बनाए गए निर्धारित काउंटरों पर फोन जमा करना होगा। इसके लिए प्रति फोन 5 रुपये शुल्क लिया जाएगा और श्रद्धालु को टोकन या रसीद दी जाएगी। फोन वापस लेते समय संबंधित विवरण का सत्यापन किया जाएगा। फोटो, वीडियो और रील्स पर रोक मुख्य वजह HR&CE मंत्री एस. रमेश के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में देवी-देवताओं की तस्वीरें और वीडियो बनाने के अलावा सेल्फी तथा सोशल मीडिया के लिए रील्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पूजा और दर्शन के दौरान अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा होने की बात सामने आई थी। विभाग ने बताया कि पलानी, तिरुचेंदूर, मदुरै और रामेश्वरम जैसे प्रमुख मंदिरों में मोबाइल संबंधी प्रतिबंध पहले से लागू रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत अब 52 प्रमुख मंदिरों में इसे व्यापक रूप से लागू किया गया है। सुरक्षित जमा होंगे मोबाइल मंदिरों में स्मार्टफोन जमा करने के लिए सुरक्षा काउंटर और लॉकर की व्यवस्था की गई है। कांचीपुरम के देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में श्रद्धालु की तस्वीर, मोबाइल का मॉडल और फोन नंबर जैसे विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद रसीद या टोकन के आधार पर फोन लौटाया जाएगा। तिरुवन्नामलाई सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भी इसी तरह की व्यवस्था शुरू की गई है। 5 रुपये शुल्क का मकसद क्या? HR&CE विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5 रुपये का शुल्क मंदिरों के लिए अतिरिक्त आय जुटाने के उद्देश्य से नहीं लिया जा रहा है। मंत्री के अनुसार यह राशि मोबाइल जमा करने की व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों, सुरक्षित लॉकर और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संचालन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।

हरियाणा बैंक घोटालाः 19 पर CBI की तीसरी चार्जशीट

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

पंचकूला, 2 सितंबर 2026। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े करीब 504 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल की। पंचकूला स्थित उइकमामलों की विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र में हरियाणा कैडर के

छह क्ष्अर अधिकारियों समेत IDFC फर्स्ट बैंक और अव स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। CBI के अनुसार तीसरी चार्जशीट में छह IAS अधिकारी, IDFC फर्स्ट बैंक के तीन अधिकारी, अव स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारी शामिल हैं। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, खातों में हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और उकसाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। बैंक अधिकारियों से मिलीभगत का आरोप जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने दोनों बैंकों के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर सरकारी धन को निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत स्थानांतरित कराया। उइकके मुताबिक हरियाणा सरकार के आठ विभागों और संस्थानों की राशि चिन्हित बैंक शाखाओं में जमा कराई गई और बाद में कथित तौर पर ऐसे तीसरे पक्ष के खातों में स्थानांतरित की गई, जिनका संबंधित सरकारी विभागों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। CBI का कहना है कि इस प्रक्रिया में वित्त विभाग के वित्तीय सावधानी और धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी दिशा-निदेर्शों का कथित उल्लंघन हुआ। एजेंसी के मुताबिक रकम को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से इधर-उधर कर उसकी लेयरिंग की गई और बाद में नकदी में बदला गया। आठ सरकारी विभागों की राशि प्रभावित जांच में पंचायत विभाग, पंचकूला एवं कालका नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित आठ सरकारी विभागों एवं संस्थानों की राशि प्रभावित होने की बात सामने आई है। CBI के अनुसार अब तक करीब 504 करोड़ रुपये के कथित गबन का पता चला है। एजेंसी का दावा है कि इस मामले में आरोपियों ने कथित रूप से अवैध आर्थिक लाभ हासिल किया।

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at Maruthi"Plaza", No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, Advertisement 88676 89130 , RNI No. KNHIN/2026/A5540. E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026